आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 24/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एस.बी.एफ.सी. फाईनेन्स लि.शाखा कार्यालय– प्रथम तल, राजधानी ग्लास हाऊस के ऊपर, मेट्रो पिलर नं. 63 के सामने, कामा हाऊस एण्ड भौमिया जी का मंदिर, ईएसआईसी हॉस्पिटल, अजमेर रोड़, सोडाला, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अरूणोदय सिंह,
2. श्रीमती रीटा सिंह,

पता:– 948, भैहरू की ढ़ाणी, सीकर रोड़, हरमाड़ा, जयपुर

एवं प्लॉट नं. बी–74, फ्लेट नं. जी–2, ग्राउण्ड फ्लोर, गिरधारीपुरा, अवधपुरी, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री गोपेश कुम्भज, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 20.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.07.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रीटा सिंह के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. बी–74, योजना अवधपुरी–बी ब्लॉक, ग्राम गिरधारीपुरा, जयपुर में ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित फ्लेट नं. जी– 2, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को बन्धक रख कुल राशि 22,49,031/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 14.06.2019 को अप्रार्थी का ऋण खाता प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.11.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का मलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 22,49,031/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 24,51,057/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रीटा सिंह के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. बी–74, योजना अवधपुरी–बी ब्लॉक, ग्राम गिरधारीपुरा, जयपुर में ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित फ्लेट नं. जी– 2, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 20.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner